









सागर, सोमवार 4 सितम्बर 2023

संस्थापक-संपादक : स्व. मायाराम सुरजन

## देश को संशय में डालती मोदी सरकार

संसदीय परम्पराओं की अवहेलना करने की आदी हो चुकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने अपनी इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए देश के इतिहास में पहली बार ट्रिक्ट के जरिये संसद का विशेष सत्र बुलाकर सांचित कर दिया है कि वह न केवल गैरिजमंदार है बरन उसका पारदर्शिता से भी कोई लेना-देना नहीं रह गया है। ऐसे बक्त में जब संयुक्त विपक्ष का गठबन्धन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजिव एलाएंस) मुन्हई में 31 अगस्त व 1 सितम्बर को 2024 के लोकसभा की चुनावी रणनीति में व्यस्त था, केन्द्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी कि 18 से 22 सितम्बर को विशेष सत्र होगा। भले ही इस सूचना को 'इंडिया' उपेक्षित कर अपनी कार्यवाही में लगा रहा लेकिन यह एक तरह से देश को अंधेरे में खेणे जैसा है क्योंकि यह कार्यप्रणाली किसी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की नहीं हो सकती। न ही यह 'इंडिया' को बढ़ाती एकता के जबाब में होनी चाहिए।

इस लेकर कई तरह के क्यास हैं। इसमें वर्ष 2024 में होने जा रहे लोकसभा को समय से पहले करा लेने की साम्भावना से लेकर संघीयता में संशोधन, चुनाव टाल देने या फिर मोदी को हमेसा के लिये पीएम बनाये जाने जैसी गुंजाइशें टटोली जा रही हैं। चान द्वारा नया नवकश जारी करना (जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है), मणिपुर हिंसा, गौतम अदानी को लेकर नये खुलासे, महंगाई आदि अनेक विषय हैं जिनके बारे में अनुमान व्यक्त किये जा रहे हैं कि इन मसलों पर सरकार कोई बात करना चाहती है। सही जानकारी किसी के भी पास नहीं है। फिर, हाल ही में तो संसद का सत्र हो चुका है। क्यों नहीं सरकार ने इन विषयों पर तब चर्चा कर ली? सबाल यह भी है कि क्यों लोगों या संसदों को विषय को लेकर क्यास लगाने के लिये छोड़ा जाये? क्यों नहीं सूचना का साथ ही विषय की जानकारी दे दी गई? संसद पर केवल सता का हक नहीं है, जो अन्य लोगों को इसकी सूचना से चर्चित रखा जाये। यह सत्र 5 दिनों का बच्चा है, जबकि विशेष सत्र एकाध दिन के ही होते हैं। दुर्भाग्य से तमाशों के आयोजनों में पारंगत मोदी सरकार इसे भी इंटरेंट बना रही है।

आखिरकार क्यास सत्र कोई मजाक नहीं होता और न ही उसे सत्तापक्ष का कोई विशेषाधिकार समझा जाये, बावजूद इसके कि सरकार को ऐसा करने का पूरा हक है। तो भी इस अधिकार का प्रयोग बहुत गम्भीरता से; और बेहद खास उद्देश्यों को लेकर होना चाहिए। विशेष सत्र का विषय क्या है, वह किन परिस्थितियों में आयोजित किया जा रहा है और इसे बुलाये जाने का प्रयोजन क्या है—वह सारा कुछ सरकार को बलाला चाहिये था। यह सूचना प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से तथा बाकायदा एक अधिसूचना जारी कर नागरिकों को देनी थी। संसद पर पहला हक तो नागरिकों का होता है, चाहे वे स्वर्वं इसके प्रत्यक्ष सदस्य न हों। जो सदस्य दोनों सदनों में बैठते हैं वे अंततः जनसामान्य की ही नुमाइंदगी करते हैं। सरकार को पहले तो इस पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिये थी फिर अपना उद्देश्य बलाला चाहिये था।

मोदी सरकार द्वारा संसदीय गरिमा व परम्पराओं को ध्वस्त करने की पूरी शूरूला है, जिसकी एक और कड़ी का सब्जन इसी एपीयोड से है। सरकार ने एक समिति बनाई है जो 'एक देश एक चुनाव' की योजना बनाकर सरकार को सौंपेगी। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को किसी समिति का अध्यक्ष बनाकर सरकार के किसी विभाग को रिपोर्ट सौंपें की जिम्मेदारी दी गई है जो कभी सिर्फ उस विभाग का नहीं वरन् पूरी सरकार का प्रमुख हुआ करता था। वास्तविकता में चाहे न हो लेकिन संवैधानिक परिभाषा के अनुसार तो वह राष्ट्रध्यक्ष ही है जिसके अधीन पूरी देश होता है। संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत खुद मोदी इन्हीं राष्ट्रपति के अंतर्भाव काम कर चुके हैं। न यह कोई पूछें वाला है और न ही कोई बताने वाला कि आखिर एक पूर्व राष्ट्रपति कैसे किसी समिति का प्रमुख बनकर सरकार को कोई रिपोर्ट दे सकता है। काफ़ा दे से तो कोई व्यक्ति जिस दिन इस पद पर पहुंचता है, उसी दिन से वह दलगत राजनीति से ऊपर हो जाता है; पर यह सब तभी सम्भव है जब किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल की ही आंखों का नहीं, किसी सरकार की आंखों का भी नहीं, बल्कि पूरे देश की आंखों का पानी मर जाये।

अगर 'एक देश एक चुनाव' की बात करें तो यह करा पाना बहुत कठिन है—प्रशासकीय और राजनीतिक दोनों कारणों से अव्यवहारिक। आजादी के बाद हुए पहले चार आम चुनावों के साथ विधानसभाओं के निर्वाचन हुए थे परन्तु तब की परिस्थितियां अलग थीं। अबादी का मरी, चुनावी हिंसा न्यूतम थी। राजनीतिक दलों के बीच आज के जैसी वैमनस्यता भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि चुनावों का आकार व स्वरूप विशाल नहीं था। इसके बावजूद अगर सरकार एक साथ चुनाव कराना ही चाहती है तो पहले वह इसके फायदे बलाला ये। यह भी बताये कि सामान्य नागरिकों, विशेषकर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी में डाले बगैं या कैसे सम्पन्न होंगे। जब मणिपुर जैसे छोटे से राज्य की हिस्सा को रोकने में सरकार 5 माह में भी सफल नहीं होती और ज्यादातर राज्यों के चुनाव कई चरणों में कराने पड़ते हैं, तो इसने बड़े देश में एक दिन में कैसे चुनाव हो सकते हैं। यह जानने का हक नागरिकों का है; और बलाला सरकार का कर्तव्य।

3A

प बाराती जानते हैं।

तो यह मीडिया आज बाराती प्रवृत्ति का हो गया है। छिड़ा-चेपो!

इंडिया की बेहद सफल मुंबई बैंक में उसे बहुत सारी कमियां खोज ली हैं। जैसे बह बाराती सर्वशेष माना जाता है कि लोडकी बांबों के यहां जाक यह कमी निकाल सकते हैं कि उसने कोकोकाला में चाय बनाकर नहीं लिए थे। परीवर्तन या चिकन क्या बनाया?

बनाने तो परीवर्तन या चिकन की आज हमारे मीडिया को आगे बढ़ाते हुए देश के पहले चुनाव जाना है।

लेपट से उनके मतभेद की खबरें लोकसभा के मतदान

हूंडने लगे। ममता बनर्जी कहा है कि वह किए एक सितम्बर की मीडिया खत्त होते ही शिवसेना के संजय रातों ने सबसे यहले यही बताया कि आपके समाने प्रेस कांफ्रेंस में सब नेता मीडिया हैं। ममता बनर्जी को जल्दी जाना था तो वे चतुर गई।

सोनिए जो ममता एक सितंबर की खबर मीडिया सूचना से पहले सेवनीयां को शाल उड़ाकर उनका समान कर रही थीं। बैंगलूरु की प्रेस कांफ्रेंस में माय फेवरेट राहल कर रही थीं। वे किसी छोटी बात से नाराज होकर जा सकती थीं।

लेपट से उनके मतभेद की खबरें लोकसभा के मतदान

## इंडिया की सफलता से बौखलाया मीडिया

में सबसे तेज निकल रहा एंकर बैंचारा यह भी नहीं कह पाया कि हास्पी एप्सर्स में कौन सी कमी रह गई।

बाकी एंकर और प्रकार अभी यह नहीं सोच पारे कि कभी उनसे भी उत्तर जैनतों के मालिक ही पूछेंगे कि यह नफरत उनके फैलाए थे? क्या हमने कहीं रुकाव कर कहा था? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। एंकर, प्रकार, मीडिया मालिक सब से सबल होगा? अभी तो कुछ राज्य सरकारों की हिम्मत की बजाए दो-चार एंकर एंकर ही जेल में गए लेकिन आप विपक्ष की खासतीर से कैरियर की जगह सरकार तो लोकसभा में खड़े भागीदारी से डरना छोड़ दें तो बड़ी तात्पद में मीडिया को कानूनी कार्रवाई का समान करना पड़ेगा। यिन्होंने जाकर बैंचारा के मामले में क्या बोला?

लेपट से उनके मतभेद की खबरें लोकसभा के मतदान

हूंडने लगे। ममता बनर्जी कहा है कि वह नहीं बोलने नहीं दे रहा है।

एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में केमेटी बना रहे हैं। मगर मणिपुर के अपने केन्द्रीय मंत्री, वहां के दूसरे सांसद को अपने ही देश की लोकसभा में बोलने नहीं दे रहा है। संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया व्यापक रूप से बोलने नहीं जाएगी? वह भी तो देश का हिम्मत है। क्या यह सब बातें विदेशी अतिथियों के कानों में नहीं जाएंगी? इन परिस्थितियों में इंडिया आकार ले रहा है। जाहिर है एक बड़ा चैलेज बन गया है।

लेपट से उनके मतभेद की खबरें लोकसभा के मतदान

हूंडने लगे। ममता बनर्जी को बोलने नहीं दे रहा है।

एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में केमेटी बना रहे हैं। मगर मणिपुर के अपने केन्द्रीय मंत्री, वहां के दूसरे सांसद को अपने ही देश की लोकसभा में बोलने नहीं दे रहा है। संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया व्यापक रूप से बोलने नहीं जाएगी? वह भी तो देश का हिम्मत है।

लेपट से उनके मतभेद की खबरें लोकसभा के मतदान

हूंडने लगे। ममता बनर्जी को बोलने नहीं दे रहा है।

एक देश एक चुनाव के लिए एक बड़ा चैलेज बन गया है। जो कमेटी बना रही है, वह नहीं जाएगी। एक देश की लोकसभा में बोलने नहीं दे रहा है। एक देश की लोकसभा में बोलने नहीं दे रहा है।

लेपट से उनके मतभेद की खबरें लोकसभा के मतदान

हूंडने लगे। ममता बनर्जी को बोलने नहीं दे रहा है।

एक देश एक चुनाव के लिए एक बड़ा चैलेज बन गया है। जो कमेटी बना रही है, वह नहीं जाएगी। एक देश की



गंग के सरपंच और सचिव सहित अधिकारियों पर जेसीबी मशीन से काम निपटाने का आरोप

## 2 मजदूरों ने 12 दिनों में बना दिया डग प्लाइंट



अखेंड यादव

बल्देवगढ़, देशबन्धु। जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चेंटरी खास में सरपंच एवं सचिव द्वारा शासन के उद्घंघन कर मनमाने होंगे से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। शासन द्वारा ग्राम पंचायत के लाखर से डग प्लाइंट का निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसका निर्माण कार्य में मनमानी किए जाने शिकायत ग्रामीणों ने जनपद सीईओ से की गयी है।

सचिव द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामों में पानी के छारवाट एवं मजदूरों को ग्राम में ही मजदूरी देने के लिए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए लाखों रुपयों की गश मनमाना योजना से स्वीकृत करती है। जिससे ग्रामीणों को पानी के संकट में कुछ हद तक राहत मिल सके। मजदूरों को गांव में मजदूरी





# जन आशीर्वाद यात्रा

## भव्य शुभारंभ



यात्रा क्र.	संभाग	प्रारंभ स्थान	दिनांक	मुख्य अतिथि
1	रीवा	चित्रकूट	3 सितंबर 2023	श्री जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष
2	उज्जैन	नीमच	4 सितंबर 2023	श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षामंत्री
3	जबलपुर	मंडला	5 सितंबर 2023	श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
4	चंबल	श्योपुर	5 सितंबर 2023	श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
5	इंदौर	खंडवा	6 सितंबर 2023	श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री

10,643 किमी की यात्रा > 998 स्थान पर स्वागत > 678 दूर सभा > 211 मंच सभा > 50 बड़ी सभा

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती 25 सितंबर के पावन अवसर पर

पांचों यात्राओं का भोपाल में समागम एवं कार्यकर्ता महाकुंभ होगा

जिसमें लाखों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे

देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी  
कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे

भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश



फिर इस बार भाजपा सरकार